(b) whether it is also a fact that only 15% capacity of the plant is being utilised and the vaccine manufactured proved to be defective and ineffective ;

(c) whether Government have made any inquiry into the matter ;

(d) if so, what is the outcome thereof stating the action taken/ proposed to be taken by Government in this regard ; and

(e) if answer to part (c) above be in the negative, whether Government propose to hold any CBI inquiry into the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV) : (a) The erstwhile Indian Dairy Corporation set up a Foot and Mouth Disease Vaccine Plant at Gachibowli near Hyderabad at a total investment of approximately Rs. 23 crores. After the merger of Indian Dairy Corporation with National Dairy Development Board (NDDB) the plant has become a managed unit of NDDB.

(b) The Foot and Mouth Disease Vaccine Plant, Hyderabad has already reached a capacity utilisation of over 40% of the installed capacity for Foot and Mouth Disease (FMD) vaccine production. The vaccine manufactured by this Plant uses technology acquired from the Welcome Foundation of the U.K. and is the first highly concentrated, BHK Tissue culture FMD vaccine in the country, and is of excellent quality.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

(e) There is no proposal under consideration of the Government to hold an inquiry.

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

1283. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को, वर्ष-वार, कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) अब तक राज्यों द्वारा वस्तुत: कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है ; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों के बारे में पूरी सूचना 1985–86 और 1986–87 के लिए उपलब्ध है । तथापि, 1987–88 और 1988–89 के वर्षों के लिए केवल अनन्तिम सूचना ही उपलब्ध है । अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए किए गए वर्ष-वार आवंटनों और राज्यों द्वारा उपयोग

की गई निधियों के ब्यौर नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	आवंटन	उपयोग की गयी निधियां	प्रतिशत उपयोग
1985–86	2064.22	1841.42	89.20
1986–87	2241.33	2406.96	107.28
1987–88	2089.26 (संशोधित)	2052.03*	98.22
1988–89	2233.98	1979.78*	88.62

*अनन्तिम

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की कुछ योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं, जिनका कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधियों में से किया जाता है और इनकी निगरानी भी राज्यों द्वारा की जाती है । तथापि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण जल सप्लाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और उन्नत किस्म के चूल्हों जैसी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की कुछ योजनाओं के संबंध में सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में निष्पादन लक्ष्यों से कम रहा है :—

आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कुछ उत्तर पूर्वी राज्य (असम; मणिपुर, मेघालय, मिजोरम; नागालैंड) तथा त्रिपुरा निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप के दूर दराज के संघ शासित क्षेत्र ।

(घ) कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ।

देश में बीड़ी मजदूरों का शोषण

1284. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 40 लाख बीड़ी मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और यह कि उद्योगपतियों द्वारा उनका अत्यधिक शोषण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार रखती है जो कि इस मामले की जांच करेगी और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) और (ख) बीड़ी विनिर्माण को असंगठित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीड़ी उद्योग में कर्मकारों की दशा पहले से अध्ययनों की विषय-वस्तु रही है । विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों तथा सिफा-